



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156 ]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 26, 2002/आषाढ़ 5, 1924

No. 156]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 26, 2002/ASADHA 5, 1924

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग )

( पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय )

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2002

विषय : चीन जनवादी गणराज्य तथा सिंगापुर मूल के अथवा वहां से निर्यातित डी ( - ) पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल गलाइसिन मिथाइल पोटेशियम डेन साल्ट के भारत में आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करना ।

सं. 14/23/2002-डीजीएडी.— मै0 दौराला आर्गेनिक्स लि0, दौराला, उ0प्र0 ने 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी गया गया है) के समक्ष याचिका दायर की है जिसमें चीन जनवादी गणराज्य तथा सिंगापुर, (जिन्हें इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डी(-)पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल गलाइसिन मिथाइल पोटेशियम डेन साल्ट के पाटन का आरोप लगाया गया है तथा पाटनरोधी जांच करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है ।

## 1. विचाराधीन उत्पाद

मौजूदा जांच में विचाराधीन उत्पाद ' डी(-) पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल गलाइसिन मिथाइल पोटेशियम (जिसे डी(-)अल्फा पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल गलाइसिन डेन साल्ट (मिथाइल पोटेशियम)

के रूप में जाना जाता है), डी(-)अल्फा पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन डेन साल्ट (मिथाइल पोटेशियम), डी(-)अल्फा पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन डेन साल्ट (मिथाइल पोटेशियम), डी(-)अल्फा पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन मिथाइल पोटेशियम डेल साल्ट, डी(-)अल्फा पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन मिथाइल एसीटो एसीटेट पोटेशियम, साल्ट \* है (जिसे इसके बाद सम्बद्ध सामग्री/पीएचपीजीडीएस कहा गया है)। मुख्य रूप से डी(-)पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन बेस का भारत में आयात किया जाता है जिसे विभिन्न विनिर्माताओं/आयातकों द्वारा पीएचबीजीडीएस में परिवर्तित किया जाता है और इसका उपयोग अमैक्सोलीन (बल्क औषधि) तथा सिफाड्रोक्सिल के उत्पादन के लिए किया जाता है।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि पीएचपीजीडीएस का वर्गीकरण अन्य कार्बनिक मिश्रण की श्रेणी में सीमाशुल्क अध्याय 29.42 के तहत किया जाता है। पीएचपीजीडीएस का वर्गीकरण सीमाशुल्क उपशीर्ष सं० 2942.00 के तहत किया जाता है। आईटीसी के 8 अंकीय वर्गीकरण के अनुसार, पीएचपीजीडीएस का वर्गीकरण अन्य श्रेणी अर्थात् 2942,0008 के तहत किया जाता है।

उन्होंने आगे इस बात का उल्लेख किया है कि डीजीसीआईएंडएस से आयात के मासिक आंकड़े केवल नवम्बर, 2001 तक के लिए उपलब्ध हैं। पाटन की मात्रा में बढ़ोतरी मुख्यतः जुलाई, 2001 से हुई है जब याचिकाकर्ता ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है और इसमें चीन तथा सिंगापुर पर पीएचपीजी बेस पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद और वृद्धि हुई है। विभिन्न शुष्क पत्तनों से होने वाले आयातों को सामान्यतः डीजीसीआईएंडएस द्वारा दिए गए आंकड़ों में दर्शाया नहीं जाता है। इसके अतिरिक्त डीजीसीआईएंडएस के आयात संबंधी आंकड़ों में अन्य डेन साल्ट भी शामिल हैं जिसे सम्बद्ध वस्तुओं के साथ ही मिला दिया गया है।

चूंकि पीएचपीजी डेन साल्ट के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों में आयात संबंधी अनन्य आंकड़ों का उल्लेख नहीं है, इसलिए, याचिकाकर्ता को गौण स्रोत अर्थात् इंटरनेशनल बिजनेस इन्फार्मेशन सर्विसेज, मुंबई के आंकड़ों पर ही निर्भर रहना पड़ा है। एजेंसी द्वारा उपलब्ध किए गए आंकड़े करस्टम डेली लिस्टों पर आधारित हैं।

## 2. घरेलू उद्योग

यह याचिका मै० दौरला आर्गेनिक्स लि० एसपीएल लि० द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वे भारत में सम्बद्ध वस्तु के एक मात्र उत्पादक हैं। अतः याचिकाकर्ता प्रथम दृष्टया उपरोक्त नियमों के नियम 5(3) (क) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने के आधार संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

### 3. शामिल देश

मौजदा जांच में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य तथा सिंगापुर है ।

### 4. समान वस्तु

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तु के समान वस्तु है । इसलिए, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तु को उपरोक्त नियमों के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है ।

5. सामान्य मूल्य: प्राधिकारी इस बात को नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने उत्पादन की परिकलित लागत के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य में सम्बद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का दावा किया है जिसमें चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में मानते हुए समुचित समायोजन भी किए गए हैं। प्राधिकारी का यह प्रस्ताव है कि यथासंशोधित पाटनरोधी नियमों के अनुबंध IX के पैरा (7) और (8) के मध्यनजर याचिकाकर्ता के दावे की जांच की जाए । प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य में सम्बद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य पर विचार किया है । जहां तक सिंगापुर का संबंध है, याचिकाकर्ता अपनी घरेलू बिक्रियों तथा सम्बद्ध वस्तु की तीसरे देश को हुई बिक्रियों के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं कर सका है । उन्होंने सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए उत्पादन की परिकलित लागत हेतु गणना प्रस्तुत की है । प्राधिकारी ने परिकलित सामान्य मूल्य के आधार पर सिंगापुर में सम्बद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य पर विचार किया है ।

### 6. निर्यात कीमत

याचिकाकर्ताओं ने आंकड़ों के गौण स्रोतों अर्थात् मै0 इंटरनेशनल बिजनेस इन्फार्मेशन सर्विस, मुंबई के आधार पर सम्बद्ध देशों से निर्यात कीमत का दावा किया है, जिनके आंकड़े कस्टम्स डेली लिस्ट पर आधारित होते हैं । गौण स्रोत के आंकड़ों से याचिकाकर्ता ने विवरण के आधार पर आंकड़ों को छांटा है और उनमें विचाराधीन उत्पाद के सौदों को शामिल किया है । कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, निर्यात के देश में स्वदेशी परिवहन, पत्तन हैंडलिंग तथा पत्तन प्रभारों के लिए समायोजनों का दावा किया गया है ।

### 7. पाटन मार्जिन

इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि सम्बद्ध देशों में सम्बद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य

कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि सम्बद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा सम्बद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

**8. क्षति एवं कारणात्मक संबंध:**

क्षति से संबंधित विभिन्न संकेतकों जैसे बिक्री प्राप्ति में कमी, लाभप्रदता में गिरावट, कीमत ह्रास, कम क्षमता उपयोग, संबद्ध देशों से हुए आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि, संबद्ध वस्तु की बिक्री से उचित और युक्तिसंगत कीमत न मिलने की वजह से घरेलू उद्योग को हुए घाटे से समग्र तथा संचयी रूप से प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

**9. पाटनरोधी जांच का आरंभ:**

उपरोक्त पैराग्राफों को देखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी सम्बद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु की आरोपित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच आरंभ करते हैं।

**10. जांच की अवधि:**

वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 जुलाई, 2001 से 31 मार्च, 2002 तक की है।

**11. सूचना देना:**

संबद्ध देशों में निर्यातकों और भारत में आयातकों, जिन्हें इस जांच से संबंधित समझा जाता है, को अलग से लिखा जा रहा है कि वे निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से संबंधित सूचना भेजें और अपने विचारों से अवगत कराएं। उपरोक्त नियमों के नियम 6(5) के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच के अधीन वस्तु के औद्योगिक उपयोक्ताओं तथा प्रतिनिधि उपभोक्ता संगठनों को भी अवसर प्रदान किया जा रहा है जो ऐसी सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं जो पाटन, क्षति तथा कारणात्मक संबंध के बारे में जांच से संगत हो। कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी नीचे निर्धारित समयावधि के भीतर जांच से संबंधित अनुरोध कर सकती है।

**12. समय सीमा:**

वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुंच जानी

चाहिए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों तथा आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिन के भीतर सूचना प्रस्तुत करनी होगी। यह नोट किया जाए कि निर्धारित समय सीमा में वृद्धि के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

### 13. अगोपनीय सारांश

सभी हितबद्ध पार्टियों को पाटनरोधी नियम 7(2) के अनुसार दी गई किसी भी सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करना चाहिए। यह सूचना नियम 7(1) और 7(2) के अनुसार स्वीकार की जाएगी।

### 14. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण:

नियम 6(7) के अनुसार, कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं। यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समयावधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी, अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

एल. बी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties)

### INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2002

**Subject :** Initiation of Anti-dumping investigation concerning imports into India of D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Methyl Potassium Dane Salt originating in or exported from China PR and Singapore.

Bo 601

**No. 14/23/2002-DGAD.**— M/s Daurala Organics Limited, Daurala, U.P. has filed a petition in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) alleging dumping of D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Methyl Potassium Dane Salt originating in or exported from Peoples' Republic of China and Singapore (hereinafter referred to as subject countries) and requested for initiation of Anti Dumping investigations and levy of anti dumping duties.

### 1. PRODUCT UNDER CONSIDERATION:

The product under consideration in the present petition is "D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Methyl Potassium (also known as D (-) Alpha Para Hydroxy Phenyl Glycine Dane Salt(Methyl Potassium), D(-) Alpha Para Hydroxy Phenyl Glycine Dane Salt(Methyl Potassium), D (-) Alpha Para Hydroxy Phenyl Glycine Methyl Potassium Dane Salt, D (-) Alpha Para Hydroxy Phenyl Glycine Methyl Aceto Acetate Potassium Salt " (hereinafter referred to as subject material/PHPGDS ). Predominantly D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base is imported in India which is converted to PHPGDS by various manufacturers/importers and are used for the production of Amoxycillin (bulk drug) and Cefadroxyl.

Petitioners have claimed that PHPGDS is classified under Customs chapter 29.42 in the category of Other Organic compound. PHPGDS is classified under Customs sub-heading no. 2942.00. As per ITC eight-digit classification PHPGDS is classified in others category i.e. in 2942.0008.

They have further mentioned that the monthly statistics of imports from DGCI&S is available only up to Nov 2001. The intensity of dumping increased basically from July 2001 when petitioner has started its commercial production and it got further aggravated after imposition of Anti Dumping duty on PHPG Base on China and Singapore. Imports from various dry ports are usually not reflected in the statistics provided by DGCI&S. Additionally, the import data indicated by DGCI&S includes other Dane Salt also which have been clubbed with the subject Goods.

Since for PHPG Dane Salt the DGCI&S data does not give the exclusive imports data, petitioner has relied upon the data of secondary source i.e. from International Business Information Services, Mumbai. The data provided by the agency is based on Customs Daily Lists.

### 2. DOMESTIC INDUSTRY

The petition has been filed by M/s Daurala Organics Limited SPL Ltd., The petitioner has claimed that they are the sole producer of subject material in India. Prima facie the petitioners satisfy the criteria of standing to file the petition on behalf of the Domestic Industry in terms of Rule 5(3) (a) of the Rules supra.

### 3. COUNTRIES INVOLVED:

The countries involved in the present investigation are the China PR and Singapore.

### 4. LIKE ARTICLE:

The petitioner has claimed that the goods produced by them are Like Article to the goods originating in or exported from subject countries.

Therefore, for the purpose of the present investigation, the goods produced by the petitioners are being treated as 'like articles' of the product imported from the subject countries within the meaning of the Rules supra.

#### 5. NORMAL VALUE:

The Authority notes that the petitioner has claimed normal value of subject goods in PR China on the basis of constructed cost of production with appropriate adjustments treating China as Non-Market economy. The Authority proposes to examine the claim of the petitioner in the light of Para (7) and (8) of the Annexure I of the Anti dumping rules as amended. The Authority has prima facie considered the normal value of subject goods in PR China on the basis of constructed cost of production as made available by the petitioner. As regards Singapore the petitioner has not been able to get any information about their domestic sales and third country sales of subject goods. They have submitted the calculation for constructed cost of production for normal value determination. The Authority has prima facie considered normal value of subject goods in Singapore on the basis of constructed normal value.

#### 6. EXPORT PRICE:

The petitioners have claimed the export price from the subject countries based on the secondary data sources, i.e. M/s International Business Information Service, Mumbai whose data is based on the Customs Daily List. From the data of secondary source, the petitioners have sorted the data on the basis of description and clubbed the transactions for the product under consideration. Adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation in the country of exports, port handling and port charges to arrive at the Export Price at ex-factory level.

#### 7. DUMPING MARGIN

There is prima facie evidence that Normal Value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the ex-factory export price indicating prima facie that the subject goods are being dumped by exporters from the subject countries.

#### 8. INJURY AND CAUSAL LINK

Various parameters relating to injury such as the decline in the sales realisation, decline in profitability, price suppression, lower utilisation of capacity, increase in market share of imports from subject countries and losses to the Domestic Industry due to non-realisation of fair and reasonable price from the sale of the subject goods, prima facie indicate collectively and cumulatively that the Domestic Industry has suffered material injury on account of dumping.

#### 9. INITIATION OF ANTI DUMPING INVESTIGATIONS

The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

#### 10. PERIOD OF INVESTIGATION

The Period of Investigation for the purpose of the present investigation is 1<sup>st</sup> July 2001 to 31<sup>st</sup> March 2002.

#### 11. SUBMISSION OF INFORMATION

The exporters in the subject countries and the importers in India known to be concerned with this investigation are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties, Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, Government of India, Udyog Bhavan, New Delhi – 11 00 11.

As per Rule 6(5) of Rule supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the article under investigation, and to representative consumer organizations who can furnish information which is relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limit set out below.

#### 12. TIME LIMIT

Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately are however required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately. It may be noted that no request whatsoever shall be entertained for extension in the prescribed time limit.

#### 13. NON- CONFIDENTIAL SUMMARY:

All interested parties must provide a non-confidential summary of any information provided on a confidential basis in terms of Anti-Dumping rule 7 (2). This information will be subject to acceptance in terms of Rules 7(1) and 7(2).

#### 14. INSPECTION OF PUBLIC FILE

In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interest party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority